करोना संक्रमण से 7 और मरीजों की मौत

नयी दिल्ली, 05 जून। देशभर में करोना संक्रमण धीरे-धीरे बढ़ रहा है और कुल सक्रिय मामलों की संख्या गुरुवार सुबह बढ़ कर 4866 तक पहुंच गयी। पिछले 24 घंटों में इसके संक्रमण से सात और मरीजों की मौत होने से मृतकों की संख्या 51 पहुंच गयी है।

केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से जारी

- **देश भर में करोना के एक्टिव केस 4866 हैं और मृतकों की संख्या अब 51 हो गई है।**

आंकड़ों के अनुसार, आज सुबह आठ बजे तक देश में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या बढ़ कर 4866 पहुंच गयी। अभी तक 3955 मरीजों को स्वस्थ्य होने पर उन्हें अस्पताल से छुट्टी मिल चुकी है और एक जनवरी से अब तक 51 लोगों की मौत हुई है।

भारत में ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

के प्रमुख संरचनात्मक खंडों के निर्माण के लिए एक अत्याधुनिक उत्पादन सुविधा स्थापित करेगी, जिसमें पूरी बॉडी का निर्माण किया जायेगा।

भारत की विदेश नीति को भारी झटका, स.रा. सुरक्षा परिषद में पाकिस्तान को मिले दो पद

कांग्रेस ने इस मुद्दे पर मोदी सरकार को घेरा है

-डॉ. सतीश मिश्रा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 5 जून। पाकिस्तान को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (युनाइटेड नेशन्स सिक्युरिटी काउन्सिल, यू.एन.एस.सी) में दो प्रमुख पद मिलने से भारत को आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान को बेनकाब करने के अपने प्रयासों में बड़ा झटका लगा है। इस बीच रूस ने भी पुष्टि की है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से फोन पर बातचीत के दौरान हालिया भारत-पाकिस्तान संघर्ष में अपनी भूमिका का ज़िक्र किया था।

पाकिस्तान को यू.एन.एस.सी. की तालिबान प्रतिबंध समिति का अध्यक्ष और आतंकवाद-रोधी समिति का उपाध्यक्ष चुना गया है। भारत की विदेश नीति को लगे इस झटके ने कांग्रेस को मोदी सरकार पर हमला बोलने का मौका दे दिया। कांग्रेस ने नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार पर तीखा हमला करते हुए इसे भारत की विदेश नीति के पतन की दुखद कहानी बताया।

एक्स पर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने पाकिस्तान को हाल में आई.एम.एफ. और विश्व बैंक से मिले ऋण और सुरक्षा परिषद में मिले पदों का हवाला देते हुए भारत की विदेश नीति पर सवाल उठाए।

- **कांग्रेस का कहना है, पहले पाकिस्तान को विश्व बैंक, आई.एम.एफ. तथा एशियन विकास बैंक से कर्ज़ मंजूर हुआ और अब इसे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में दो बड़े पद मिले हैं, यह भारत की विदेश नीति की भारी विफलता है।**
- **कांग्रेस ने इसके लिए वैश्विक समुदाय की भी आलोचना की और कहा, इस तरह से पाक प्रायोजित आतंकवाद को वैधता प्रदान की जा रही है।**
- **पाकिस्तान को यू.एन. सिक्यूरिटी काउन्सिल तालिबान सैंक्शन कमेटी का चेयरमैन बनाया गया है और सबसे बड़ी विडम्बना यह है कि उसे काउन्टर टैररिज़्म कमेटी का उपाध्यक्ष भी बनाया गया है।**

उन्होंने वैश्विक समुदाय पर भी पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद को वैधता देने के लिए हमला बोला।

खेड़ा ने एक्स पर लिखा, निस्संदेह, यह हमारी अपनी विदेश नीति के पतन की दुखद कहानी है, लेकिन वैश्विक समुदाय पाकिस्तान द्वारा आतंकवाद के प्रायोजन को लगातार वैधता कैसे दे सकता है?

9 मई को जब भारत और पाकिस्तान टकराव की स्थिति में थे, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष आई.एम.एफ. ने पाकिस्तान को एक अरब डॉलर का ऋण मंजूर किया।

ऑपरेशन सिंदूर के बाद केंद्र सरकार ने सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडलों की सात टीमों को पाकिस्तान के आतंकवाद समर्थन को उजागर करने और यह संदेश देने के लिए कई देशों में भेजा था कि भारत की सैन्य कार्रवाई पहलगाम हमले के जवाब में पाकिस्तान और पीओके में आतंकी ढांचों को ध्वस्त करने के लिए थी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद विश्व बैंक और एशियाई विकास बैंक ने भी पाकिस्तान को क्रमश: 40 अरब डॉलर और 800 मिलियन डॉलर के ऋण मंजूर किए।

क्रैमलिन के एक सहयोगी के अनुसार, हाल ही में पुतिन और ट्रंप की टेलीफोन पर हुई बातचीत में हालिया भारत-पाक संघर्ष का मुद्दा भी शामिल था। बुधवार को हुई इस बातचीत के बारे में जानकारी देते हुए क्रैमलिन सहयोगी यूरी उशाकोव ने बताया कि दोनों नेताओं ने यूक्रेन सहित कुछ अन्य मुद्दों पर चर्चा की।

रूस की राज्य समाचार एजेंसी टास (टी.ए.एस.एस.) के अनुसार, उशाकोव ने कहा, उन्होंने (ट्रंप-पुतिन) मध्य पूर्व और भारत-पाकिस्तान के बीच सशस्त्र संघर्ष पर भी बात की, जिसे राष्ट्रपति ट्रंप की व्यक्तिगत भागीदारी से रोका गया।

हालाँकि, उशाकोव ने बातचीत का विस्तृत ब्यौरा साझा नहीं किया।

ट्रंप पहले भी कई बार यह दावा कर चुके हैं कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध होने से रोका।

तथापि, भारत का हमेशा से यह कहना रहा है कि पाकिस्तान के साथ संघर्ष विराम का समझौता दोनों सेनाओं के डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस (डी.जी.एम.ओ.) के बीच प्रत्यक्ष बातचीत के माध्यम से हुआ था।

इस बीच, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज़ शरीफ़ ने राष्ट्रपति पुतिन से भारत के साथ विवाद को सुलझाने में मदद करने की अपील की है, यह जानकारी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के विशेष सलाहकार सैयद तारिक फातिमी ने दी।

मंगलवार को मॉस्को में रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से मुलाकात के दौरान फातिमी ने शहबाज़ शरीफ का पत्र पुतिन को सौंपा। उनकी यह यात्रा डीएमके सांसद कनिमोई करुणानिधि के नेतृत्व में गए बहुदलीय भारतीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल की अत्यंत सफल रूस यात्रा के कुछ ही दिन बाद हुई, जहाँ उन्होंने पाकिस्तान प्रायोजित सीमा पार आतंकवाद के प्रति जागरूकता फैलाई और भारत की आतंकवाद के प्रति ज़ीरो टॉलरेंस की नीति को रूस का ठोस समर्थन दिलवाया।

पहली बार सांप्रदायिक...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

नहीं चाहते। लेकिन सबसे बड़ी समस्या यह है कि दिल्ली में कोई भी जम्मू इकाई की समस्याओं या उनके पीसीसी अध्यक्ष को लेकर उनकी शिकायतों और आपत्तियों पर ध्यान नहीं दे रहा है।

एआईसीसी के जम्मू-कश्मीर प्रभारी नासिर हुसैन दिखाई ही नहीं देते और कांग्रेस की आंतरिक समस्याओं को सुलझाने के लिए कोई ठोस पहल करते प्रतीत नहीं होते। कर्रा को राहुल गांधी ने नियुक्त किया है, लेकिन समस्या यह है कि राहुल गांधी बिना पर्याप्त जांच के फैसले लेते हैं और एक बार निर्णय ले लेने के बाद उसे बदलते नहीं हैं। कर्रा पीडीपी से सीधे कांग्रेस में लाए गए हैं और अमरनाथ विवाद के समय उन्होंने गुलाम नबी आज़ाद सरकार को गिराने में बड़ी भूमिका निभाई थी।

महबूबा मुफ्ती द्वारा भाजपा से हाथ मिला लेने के विरोध में उन्होंने पीडीपी छोड़ दी थी, इसके बाद, राहुल गांधी ने उन्हें कांग्रेस में शामिल कर लिया था। पहले उन्हें कांग्रेस कार्य समिति (सीडब्ल्यूसी) का सदस्य बनाया गया और फिर वे पीसीसी अध्यक्ष बना दिये गये।

कर्रा न तो कांग्रेस की संस्कृति को समझते हैं और न ही उनके पास कोई व्यापक राष्ट्रीय या राज्य स्तरीय दृष्टिकोण है। उनकी सोच पूरी तरह कश्मीर-केन्द्रित और अलगाववादी है, यही मुख्य कारण है, जिससे जम्मू कांग्रेस में असंतोष है।

एक वरिष्ठ नेता ने जोर देते हुये कहते हैं कि कांग्रेस पहले कभी सांप्रदायिक या क्षेत्रीय आधार पर विभाजित नहीं रही है। उनका कहना है कि भाजपा इस सांप्रदायिक रुझान का फायदा उठा रही है और कर्रा की इस सोच से भाजपा को लाभ हुआ भी है। कश्मीर में तो कांग्रेस की जगह अब एनसीपी या पीडीपी ने ले ली है। इस प्रकार कांग्रेस दोनों ओर से फँसी हुई है।

राहुल गांधी ने हाल ही में विभिन्न राज्यों में कांग्रेस में मौजूद "भाजपा स्लीपर सैल्स" को हटाने की बात कही है और पार्टी इकाइयों से वादा किया है कि वे निष्क्रिय पड़ी इकाइयों के पदाधिकारियों को बर्खास्त करेंगे।

जम्मू कांग्रेस इकाई में भी ऐसे ही आरोप हाल ही में सामने आए हैं, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। न्यायसंगत होगा कि राहुल गांधी जम्मू-कश्मीर के प्रभारी एआईसीसी नेता को निर्देश दें कि वे जाँच करें और राज्य इकाई में मौजूद स्लीपर सैल्स को चिन्हित करें। वस्तुत: राहुल गांधी भाषण तो धमाकेदार देते हैं, लेकिन उन पर अमल करने का तंत्र बेहद कमज़ोर है।

सुप्रीम कोर्ट आज ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

हस्तक्षेप के बाद उठाया गया है, जब उसने परीक्षा को दो सत्रों में आयोजित करने पर आपत्ति जताई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि परीक्षा को दो शिफ्ट में आयोजित करने से कठिनाई स्तर में असमानता हो सकती है, जिससे अभ्यर्थियों पर अनुचित प्रभाव पड़ सकता है। पीठ ने इस बात पर जोर दिया कि पूरे देश में निष्पक्षता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए परीक्षा एक ही सत्र में आयोजित की जानी चाहिए। कोर्ट ने एन.बी.ई. को निर्देश दिया था कि वह परीक्षा को एक ही शिफ्ट में आयोजित करने के लिए आवश्यक लॉजिस्टिक व्यवस्थाएँ करे। साथ ही यह भी स्पष्ट किया था कि यदि बोर्ड को यह व्यवस्था लागू करने के लिए अतिरिक्त समय की आवश्यकता हो, तो वह अदालत से पुन: समय माँग सकता है।

मुख्यमंत्री भजनलाल ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

योगदान दें। मुख्यमंत्री ने कहा, प्रधानमंत्री ने देशभर में 'एक पेड़ मां के नाम' अभियान चलाया, जिससे आमजन में पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता आई। इस अभियान से प्रेरणा लेकर पिछले वर्ष राज्य सरकार ने 7 करोड़ से अधिक पौधे लगाए।

इस अवसर पर, जमवारामगढ़ के विधायक महेन्द्र पाल मीणा ने गंगा नदी के जल का कलश मुख्यमंत्री को भेंट किया। मुख्यमंत्री ने वंदे गंगा जल संरक्षण-जन अभियान के तहत रामगढ़ बांध पर श्रमदान किया। उन्होंने जलेश्वर महादेव मंदिर में जलाभिषेक-पूजा अर्चना भी की। महिलाओं ने सिर पर कलश रखकर लोकगीत गाते हुए मुख्यमंत्री का अभिनंदन किया।

कार्यक्रम में संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल, जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत, वन एवं पर्यावरण राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) संजय शर्मा, सांसद राव राजेन्द्र सिंह, डॉ. मंजू शर्मा, विधायक बालमुकुंदाचार्य, कुलदीप धनखड़, कैलाश वर्मा, मनीष यादव, अमीन कागजी, जिला प्रमुख रमा चोपड़ा सहित, जनप्रतिनिधिगण, वरिष्ठ अधिकारीगण और बड़ी संख्या में पर्यावरण प्रेमी एवं आमजन उपस्थित थे।

राज ठाकरे ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

का फोन नंबर है।' गौरतलब है कि फिल्म निर्देशक महेश मांजरेकर के यूट्यूब चैनल को दिए गए एक साक्षात्कार में राज ठाकरे के एक बयान के बाद चचेरे भाइयों के एक साथ आने की चर्चाओं ने जोर पकड़ लिया है। इसके बाद उद्धव ठाकरे ने भी गठबंधन के प्रति अपना समर्थन जताते हुए कहा है कि महाराष्ट्र और मराठी लोगों का हित दोनों नेताओं के बीच मतभेदों से ज्यादा महत्वपूर्ण है।

भगदड़ पर सिद्धारमैया ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। सीएम सिद्धारमैया ने आगे कहा, हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश जस्टिस माइकल डीकुन्हा की अध्यक्षता में हमने एक सदस्यीय आयोग नियुक्त किया है...आरसीबी इवेंट मैनेजर, डीएनए, केएससीए, जिन्होंने उनका प्रतिनिधित्व किया, हमने उन्हें गिरफ्तार करने का निर्णय लिया है। सीएम सिद्धारमैया ने कहा- मामले की जांच के लिए हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज माइकल डी'कुन्हा की अध्यक्षता में एक सदस्यीय जांच आयोग बनाया गया है।

जातिगत जनगणना में निहित ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

और ज्यादा ताकत (संख्या बल) हासिल हो रही है।"

इस मुद्दे के केन्द्र में परिसीमन की संभावना है, अर्थात् जनसंख्या के ताजा आँकड़ों के आधार पर संसदीय क्षेत्र का आकार एवं उसकी सीमा तय किये जायेंगे। परिसीमन की मौजूदा फ्रीज़िंग (यथास्थिति) 2026 तक प्रभावी रहेगी तथा उम्मीद की जा रही है कि जातियों और उपजातियों के नये आँकड़े जारी होने के बाद, सीटों के परिसीमन को लेकर जबरदस्त मोल-भाव के लिए मंच तैयार हो जायेगा।

राजनैतिक पर्यवेक्षकों को आशंका है कि इससे उत्तर-दक्षिण के बँटने की सोच तेज हो जायेगी, क्योंकि ऐसी संभावना दिखाई दे रही है कि दक्षिणी राज्यों की सीटें कम हो जायेंगी तथा उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे ज्यादा जनसंख्या वाले राज्यों की सीटें बढ़ जायेंगी।

बिहार में जातिगत पहचान लम्बे समय से राजनैतिक रणनीति के केन्द्र में रही है तथा ऐसी उम्मीद है कि जातिगत जनगणना इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनावों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।

हालाँकि जनगणना की प्रक्रिया संभवत: नई सरकार के गठन के बाद ही पूरी होने की संभावना है, लेकिन जाति-आधारित राजनैतिक नैरेटिव सार्वजनिक चर्चाओं पर पहले से ही हावी है। विश्लेषकों का कहना है कि नये जातिगत आँकड़ों से आरजेडी-कांग्रेस गठबंधन को उल्लेखनीय फायदा हो सकता है, क्योंकि आनुपातिक प्रतिनिधित्व तथा जनसंख्या की वास्तविक जातिगत संरचना पर आधारित अनुकूल कार्यवाही को इससे पर्याप्त बल मिल सकता है।

दूसरी तरफ, भाजपा तथा बिहार में उसका वर्तमान मित्र दल जद (यू) मुश्किल में पड़ते नज़र आ रहे हैं। जहाँ नीतीश कुमार के नेतृत्व में जद (यू) जब विपक्षी गठबंधन में था, तब जातिगत जनगणना का मजबूत प्रस्तावक था, लेकिन पार्टी के एनडीए गठबंधन में शामिल हो जाने तथा राजनैतिक गणित ने उनकी स्थिति बड़ी अस्पष्ट एवं संदिग्ध बना दी है।

इस बीच भाजपा के सामने हिन्दी भाषी राज्यों में जाति-आधारित राजनीति की जमीनी स्थिति को ध्यान में रखते हुए, "सबका विकास" के विचार को आगे बढ़ाने की अपनी राष्ट्रीय छवि को संतुलित बनाये रखने की चुनौती भी है।

एक वरिष्ठ राजनैतिक विश्लेषक ने इस स्थिति को संक्षेप में प्रस्तुत करते हुए कहा, "जातिगत जनगणना एक सामाजिक ऑडिट मात्र नहीं है, यह एक राजनैतिक भूकंप है, जो आने ही वाला है। यह (जातिगत जनगणना) अगले दशक में चुनावी रणनीतियों, गठबंधन के निर्माण और शायद भारतीय लोकतंत्र की संरचना तक को एक नया आकार देगी।

राजनैतिक गहमागहमी बढ़ने के साथ ही, 16 जून की अधिसूचना के आते ही, भारतीय राजनीति के एक लंबे तथा कलहपूर्ण अध्याय की शुरुआत हो जायेगी।

यह अधिसूचना देश के संघीय ढ़ाँचे के लचीलेपन, भारतीय गणतंत्र की एकता तथा भारतीय लोकतंत्र की परिपक्वता की परीक्षा लेगी।

महेश जोशी ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

ने महेश जोशी को गिरफ्तार किया था। इस बीच जोशी की पत्नी के निधन के कारण कोर्ट ने उन्हें दो बार अंतरिम जमानत दी थी।

मार्डन मीडिया, बीकानेर के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक सोमेश शर्मा द्वारा वतन प्रेस, कुम्भाना हाऊस, हनुमान हत्था, बीकानेर से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक-राजेश शर्मा, आर.एन.आई. नं. 35214/79, **जयपुर कार्यालय:** सुधर्मा एम.आई.रोड, जयपुर। फोन: 2372634, 4103333-34, **कोटा कार्यालय :** पलायथा हाऊस, छत्रपति शिवाजी मार्ग, कोटा। फोन: 2386031, 2386032,फैक्स:0744-2386033, **उदयपुर कार्यालय:** आयड मैन रोड आयड, उदयपुर। फोन: 2413092, फैक्स : 0294-2410146, **अजमेर कार्यालय:**-राष्ट्रदूत भवन, चुंगी नाका के पास, अजमेर। फोन: 2627612, फैक्स:0145-2624665, **जालोर कार्यालय :-** जी 1/63, इन्डस्ट्रीयल एरिया, फेस प्रथम, जालोर। फोन: 226422,226423, फैक्स: 02973-226424 **हिण्डौनसिटी कार्यालय :-** जी -1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डौनसिटी। फोन: 230200, 230400, फैक्स: 07469-230600 **चूरू कार्यालय :** एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरू, फोन : 256906, 256907, फैक्स: 01562-256908